



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 8, 2006/ज्येष्ठ 18, 1928

No. 98]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2006/JYAISTHA 18, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2006

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 5क का अंतःस्थापन : मूल विनियम के विनियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5क. अनंतिम टैरिफ : अनंतिम टैरिफ या प्रभारों की अनंतिम बिलिंग, जब कभी उत्पादन या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा अनुज्ञात की जाती है या आयोग द्वारा अपने प्रस्ताव या अन्यथा द्वारा अनुज्ञात की जाती है तो वह आयोग द्वारा अनुमोदित अनंतिम टैरिफ के प्रति समायोजित की जाएगी :

परन्तु यह कि जहां इन विनियमों के अधीन प्रभारित अनंतिम टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक है वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार प्रभारित अधिक रकम पर, ऐसी अधिक रकम के संदाय की तारीख से और समायोजन की तारीख तक मासिक आधार पर संगणित प्रतिवर्ष 6 % की दर से ब्याज का संदाय करेंगे :

परन्तु यह और कि जहां प्रभारित अनंतिम टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से कम है वहां फायदाग्राही उस तारीख से कम रकम पर मासिक आधार पर संगणित प्रतिवर्ष 6 % की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेंगे जिस तारीख को अंतिम टैरिफ ऐसी कम रकम की बिलिंग की तारीख तक लागू होगा।

परन्तु यह भी कि अधिक/कम रकम आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर समायोजित की जाएगी जिसके असफल होने पर व्यक्तिग्री उपयोगिता उस दर पर शास्तिक ब्याज का संदाय करेगा जो आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाए ।”।

3. विनियम 20 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“20. ऋण ईक्विटी अनुपात : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण ईक्विटी अनुपात पर 4-1-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि जहां 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है वहां ऋण ईक्विटी अनुपात वह होगा जैसा आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए :

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां अतिरिक्त पूंजीकरण 1-4-2004 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया है और विनियम 18 के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, वहां अतिरिक्त पूंजीकरण में ईक्विटी पर निम्नलिखित रूप में विचार किया जाना होगा :—

(क) आयोग द्वारा स्वीकार अतिरिक्त पूंजी व्यय का 30% ; या

(ख) अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए वित्तीय पैकेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ईक्विटी ; या

(ग) नियोजित वास्तविक ईक्विटी,

जो भी कम हो :

परन्तु यह और कि दूसरे परंतुक के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय की दशा में, आयोग 30% से अधिक ईक्विटी पर तब विचार कर सकेगा यदि उत्पादन कंपनी आयोग का यह समाधान करने में सफल हो जाती है कि 30% अधिक ऐसी ईक्विटी का लगाया जाना साधारण जनता के हित में था ।

(2) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में जिनके लिए 1-4-2004 से पूर्व विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया गया था और जिनके 1-4-2004 से 31-3-2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70: 30 के अनुपात में ऋण ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां परियोजना के वित्तपोषण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग वहां समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकेगा जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह सुस्थापित करने के लिए समर्थ हो जाती है कि 30% से उच्चतर ईक्विटी का नियोजन साधारण जनता के हित में था :

(3) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए 1-4-2004 को या उसके पश्चात् विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, टैरिफ के प्रयोजन के लिए 70 : 30 के अनुपात में ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से अधिक है वहां 30% से अधिक ईक्विटी को काल्पनिक ऋण के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपरोक्त खंड (1), (2) या (3) के अनुसार तय की गई ऋण ईक्विटी की रकम का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर फेरफार की संगणना के लिए किया जाएगा ।”।

4. विनियम 21 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 21 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(i) ऋण पूंजी पर ब्याज --

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज विनियम 20 में उपदर्शित रीति से तय बकाया ऋण पर ऋणवार संगणित किया जाएगा ;

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण को विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण के रूप में माइनस 31-3-2004 तक आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय के रूप में निकाला जाएगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर निकाला जाएगा ;

(ग) उत्पादन कंपनी ऋण को पुनःवित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगी जिससे फायदाग्राहियों के कुल फायदे में अधिक से अधिक वृद्धि हो । ऐसे पुनःवित्तपोषण की सहबद्ध लागत फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ;

(घ) ऋण संबंधी निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनःवित्तपोषण की तारीख से दर्शित किया जाएगा और उसका फायदा फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ;

(ङ) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण में पुनःवित्तपोषण से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा कोई विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के वर्षों के दौरान टैरिफ में दिया गया अवक्षयण उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तदनुसार संगणित किया जाएगा ;

(छ) उत्पादन कंपनी ऋण के वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के मदे कोई लाभ नहीं लेंगे ;

(ज) उत्पादन कंपनी अपने स्वविवेक से ऐसे ऋण को अपने स्वयं की लागत पर स्वैप कर सकेगी जिनमें ब्याज की नियत दर वाले ऋणों के साथ ब्याज की फ्लोटिंग दर है या उसके विपरीत है और स्वैपिंग के परिणामस्वरूप लाभ या हानियों को उत्पादन कंपनी से प्रोद्भूत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि फायदाग्राही आरंभिक रूप से संविदागत ऋण के लिए, चाहे वह ब्याज फ्लोटिंग या नियत दर पर हो, ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।”।

5. विनियम 26 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“26. **विलंब संदाय अधिभार :** यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा किसी बिल (यू आई तथा वी ए आर प्रभारों से भिन्न) के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रतिमास 1.25% की दर पर विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।”।

6. विनियम 36 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“36. **ऋण ईक्विटी अनुपात :** (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण ईक्विटी अनुपात पर 4-1-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि जहां 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है वहां ऋण ईक्विटी अनुपात वह होगा जैसा आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए :

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां अतिरिक्त पूंजीकरण 1-4-2004 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया है और विनियम 34 के

अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है वहां अतिरिक्त पूंजीकरण में ईक्विटी पर निम्नलिखित रूप में विचार किया जाना होगा :—

(क) आयोग द्वारा स्वीकार अतिरिक्त पूंजी व्यय का 30% ; या

(ख) अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए वित्तीय पैकेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ईक्विटी ; या

(ग) नियोजित वास्तविक ईक्विटी,

जो भी कम हो :

परंतु यह और कि दूसरे परंतुक के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय की दशा में, आयोग 30% से अधिक ईक्विटी पर तब विचार कर सकेगा यदि उत्पादन कंपनी आयोग का यह समाधान करने में सफल हो जाती है कि 30% अधिक ऐसी ईक्विटी का लगाया जाना साधारण जनता के हित में था ।

(2) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में जिनके लिए 1-4-2004 से पूर्व विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया गया था और जिनके 1-4-2004 से 31-3-2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70: 30 के अनुपात में ऋण ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां परियोजना के वित्तपोषण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग वहां समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकेगा जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह सुस्थापित करने के लिए समर्थ हो जाती है कि 30% से उच्चतर ईक्विटी का नियोजन साधारण जनता के हित में था ।

(3) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए 1-4-2004 को या उसके पश्चात् विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, टैरिफ के प्रयोजन के लिए 70 : 30 के अनुपात में ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से अधिक है वहां 30% से अधिक ईक्विटी को कार्त्पनिक ऋण के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपरोक्त खंड (1), (2) या (3) के अनुसार तय की गई ऋण ईक्विटी की रकम का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर फेरफार की संगणना के लिए किया जाएगा ।”।

7. विनियम 38 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 38 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) ऋण पूंजी पर ब्याज —

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज विनियम 20 में उपदर्शित रीति से तय बकाया ऋण पर ऋणवार संगणित किया जाएगा ;

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण को विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण के रूप में माइनस 31-3-2004 तक आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय के रूप में निकाला जाएगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर निकाला जाएगा ;

(ग) उत्पादन कंपनी ऋण को पुनःवित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगी जिससे फायदाग्राहियों के कुल फायदे में अधिक से अधिक वृद्धि हो । ऐसे पुनःवित्तपोषण की सहबद्ध लागत फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ;

(घ) ऋण संबंधी निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनःवित्तपोषण की तारीख से दर्शित किया जाएगा और उसका फायदा फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ;

(ङ) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण में पुनःवित्तपोषण से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा कोई विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के वर्षों के दौरान टैरिफ में दिया गया अवक्षयण उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तदनुसार संगणित किया जाएगा ;

(छ) उत्पादन कंपनी ऋण के वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के मद्दे कोई लाभ नहीं लेंगे ;

(ज) उत्पादन कंपनी अपने स्वविवेक से ऐसे ऋण को अपने स्वयं की लागत पर स्वैप कर सकेगी जिनमें ब्याज की नियत दर वाले ऋणों के साथ ब्याज की फ्लोटिंग दर है या उसके विपरीत है और स्वैपिंग के परिणामस्वरूप लाभ या हानियों को उत्पादन कंपनी से प्रोद्भूत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि फायदाग्राही आरंभिक रूप से संविदागत ऋण के लिए, चाहे वह ब्याज फ्लोटिंग या नियत दर पर हो, ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।”।

8. विनियम 39 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 39 के खंड (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) पम्प भंडारण उत्पादन केन्द्रों के सिवाय सभी हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए प्राथमिक ऊर्जा की दर पूर्व वर्ष के सभी मासों के लिए संबंधित क्षेत्र के

केन्द्रीय सेक्टर ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र के निम्नतर परिवर्तनीय प्रभारों की औसत के बराबर होगा । प्राथमिक ऊर्जा प्रभार प्राथमिक ऊर्जा दर और केन्द्र की बिक्रीयोग्य अनुसूचित प्राथमिक ऊर्जा के आधार पर संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह कि उत्पादन केन्द्र के वार्षिक नियत प्रभार से अधिक उपरोक्त प्राथमिक ऊर्जा दर को लागू करके वसूलनीय प्राथमिक ऊर्जा प्रभारों की दशा में, ऐसे उत्पादन केन्द्र के लिए प्राथमिक ऊर्जा दर निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित की जाएगी :

$$\text{प्राथमिक ऊर्जा प्रभार} = \frac{\text{वार्षिक नियत प्रभार}}{\text{विक्रीयोग्य डिजाइन ऊर्जा}}$$

(3) प्राथमिक ऊर्जा प्रभार = विक्रीयोग्य अनुसूचित प्राथमिक ऊर्जा x प्राथमिक ऊर्जा दर ।

गौण ऊर्जा दर प्राथमिक ऊर्जा दर के बराबर होगी ।

गौण ऊर्जा प्रभार = बिक्री योग्य अनुसूचित गौण ऊर्जा x गौण ऊर्जा दर ।

9. विनियम 40 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 40 के खंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) वार्षिक आधार पर परिकल्पित कुल प्रोत्साहन संदाय बिक्रीयोग्य आबंटित क्षमता के आधार पर फायदाग्राहियों द्वारा विभाजित किया जाएगा ।”।

10. विनियम 44 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 44 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“44. विलंब संदाय अधिभार : यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा किसी बिल (यू आई तथा वीएआर प्रभारों से भिन्न) के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रतिमास 1.25% की दर पर विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।”।

11. विनियम 48 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 48 के खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(iv) क्षमता प्रभार फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा, जिसमें उत्पादन कंपनी के क्षेत्र के बाहर के भी सम्मिलित है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रत्येक मास और संबंधित उत्पादन केन्द्र में अपने-अपने अंशों के अनुपात में संदत्त किए जाएंगे :

ए सी सी₁ = ए एफ सी - (एस पी ई₁ + डी ई 2 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₂ = ए एफ सी - (एस पी ई₂ + डी ई 3 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₃ = ए एफ सी - (एस पी ई₃ + डी ई 4 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₄ = ए एफ सी - (एस पी ई₄ + डी ई 5 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₅ = ए एफ सी - (एस पी ई₅ + डी ई 6 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₆ = ए एफ सी - (एस पी ई₆ + डी ई 7 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₇ = ए एफ सी - (एस पी ई₇ + डी ई 8 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₈ = ए एफ सी - (एस पी ई₈ + डी ई 9 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₉ = ए एफ सी - (एस पी ई₉ + डी ई 10 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₁₀ = ए एफ सी - (एस पी ई₁₀ + डी ई 11 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₁₁ = ए एफ सी - (एस पी ई₁₁ + डी ई 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर
 ए सी सी₁₂ = (ए एफ सी - (एस पी ई₁₂) x प्राथमिक ऊर्जा दर

जहां,

ए एफ सी = वार्षिक नियत प्रभार

ए सी सी₁, ए सी सी₂, ए सी सी₃, ए सी सी₄, ए सी सी₅, ए सी सी₆, ए सी सी₇, ए सी सी₈, ए सी सी₉, ए सी सी₁₀, ए सी सी₁₁ और ए सी सी₁₂ क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, और बारहवें मास की समाप्ति तक की संचयी अवधि के लिए वार्षिक क्षमता प्रभार की रकम है।

एस पी ई₁, एस पी ई₂, एस पी ई₃, एस पी ई₁₂ क्रमशः वर्ष के पहले, दूसरे, तीसरे बारहवें मास तक एक्स-बस विक्रीयोग्य अनुसूचित प्राथमिक ऊर्जा मूल्य है ।

$$\begin{aligned}
 \text{सीसी 1} &= \text{एसीसी}_1 \times \frac{\text{डीई}_1}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 2} &= \text{एसीसी}_2 \times \frac{\text{डीई}_2}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 3} &= \text{एसीसी}_3 \times \frac{\text{डीई}_3}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 4} &= \text{एसीसी}_4 \times \frac{\text{डीई}_4}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 5} &= \text{एसीसी}_5 \times \frac{\text{डीई}_5}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 6} &= \text{एसीसी}_6 \times \frac{\text{डीई}_6}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 7} &= \text{एसीसी}_7 \times \frac{\text{डीई}_7}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 8} &= \text{एसीसी}_8 \times \frac{\text{डीई}_8}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 9} &= \text{एसीसी}_9 \times \frac{\text{डीई}_9}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 10} &= \text{एसीसी}_{10} \times \frac{\text{डीई}_{10}}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 11} &= \text{एसीसी}_{11} \times \frac{\text{डीई}_{11}}{\text{डीई}} \\
 \text{सीसी 12} &= \text{एसीसी}_{12} \times \frac{\text{डीई}_{12}}{\text{डीई}}
 \end{aligned}$$

जहां

सीसी 1, सीसी 2, सीसी 3..... सीसी 12 क्रमशः वर्ष के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे बारहवें मास तक मासिक क्षमता प्रभार है ।

डी ई = वार्षिक विक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा

डी ई 1, डी ई 2, डी ई 3..... डी ई 12 क्रमशः वर्ष के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे बारहवें मास तक एक्स-बस विक्रीयोग्य डिजाइन ऊर्जा मूल्य

निम्नलिखित के लिए जनरेटर्स को संदेय कुल क्षमता प्रभार :

पहले मास = (सी सी 1)

दूसरे मास = (सी सी 2 - सी सी 1)

तीसरे मास = (सी सी 3 - सी सी 2)

चौथे मास = (सी सी 4 - सी सी 3)

पांचवें मास = (सी सी 5 - सी सी 4)

छठे मास = (सी सी 6 - सी सी 5)

सातवें मास = (सी सी 7 - सी सी 6)

आठवें मास = (सी सी 8 - सी सी 7)

नौवें मास = (सी सी 9 - सी सी 8)

दसवें मास = (सी सी 10 - सी सी 9)

ग्यारहवें मास = (सी सी 11- सी सी 10)

बारहवें मास = (सी सी 12- सी सी 11)

और ऐसे प्रत्येक फायदाग्राही, जिनके पास उत्पादन केन्द्र की क्षमता में फर्म आबंटन है, निम्नलिखित का संदाय करेंगे :

पहले मास = [एसीसी 1 x डब्ल्यूबी 1]/100

दूसरे मास = [एसीसी 2 x डब्ल्यूबी 2- x एसीसी 1 x डब्ल्यूबी 1]/100

तीसरे मास = [एसीसी 3 x डब्ल्यूबी 3- x एसीसी 2 x डब्ल्यूबी 2]/100

चौथे मास = [एसीसी 4 x डब्ल्यूबी 4- x एसीसी 3 x डब्ल्यूबी 3]/100

पांचवें मास = [एसीसी 5 x डब्ल्यूबी 5- x एसीसी 4 x डब्ल्यूबी 4]/100

छठे मास = [एसीसी 6 x डब्ल्यूबी 6- x एसीसी 5 x डब्ल्यूबी 5]/100

सातवें मास = [एसीसी 7 x डब्ल्यूबी 7- x एसीसी 6 x डब्ल्यूबी 6]/100

आठवें मास = [एसीसी 8 x डब्ल्यूबी 8- x एसीसी 7 x डब्ल्यूबी 7]/100

नौवें मास = [एसीसी 9 x डब्ल्यूबी 9- x एसीसी 8 x डब्ल्यूबी 8]/100

दसवें मास = [एसीसी 10 x डब्ल्यूबी 10- x एसीसी 9 x डब्ल्यूबी 9]/100

$$\text{ग्यारहवें मास} = [\text{एसीसी 11} \times \text{डब्ल्यूबी 11} - \text{एसीसी 10} \times \text{डब्ल्यूबी 10}] / 100$$

$$\text{बारहवें मास} = [\text{एसीसी 12} \times \text{डब्ल्यूबी 12} - \text{एसीसी 11} \times \text{डब्ल्यूबी 11}] / 100$$

जहां--

और डब्ल्यूबी 1, डब्ल्यूबी 2, डब्ल्यूबी 3, डब्ल्यूबी 4, डब्ल्यूबी 5, डब्ल्यूबी 6, डब्ल्यूबी 7, डब्ल्यूबी 8, डब्ल्यूबी 9, डब्ल्यूबी 10, डब्ल्यूबी 11 और डब्ल्यूबी 12 क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवें मास तक की संचित अवधि के दौरान फायदाग्राही की बिक्रीयोग्य आबंटित क्षमता शेयर की भारित औसत प्रतिशतता है।

12. विनियम 54 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“54. **ऋण ईक्विटी अनुपात** : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण ईक्विटी अनुपात पर 4-1-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि जहां 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है वहां ऋण ईक्विटी अनुपात वह होगा जैसा आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए :

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां अतिरिक्त पूंजीकरण 1-4-2004 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया है और विनियम 53 के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है वहां अतिरिक्त पूंजीकरण में ईक्विटी पर निम्नलिखित रूप में विचार किया जाना होगा :--

(क) आयोग द्वारा स्वीकार अतिरिक्त पूंजी व्यय का 30% ; या

(ख) अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए वित्तीय पैकेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ईक्विटी ; या

(ग) नियोजित वास्तविक ईक्विटी,

जो भी कम हो :

परन्तु यह और कि दूसरे परंतुक के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय की दशा में, आयोग 30% से अधिक इक्विटी पर तब विचार कर सकेगा यदि उत्पादन कंपनी आयोग का यह समाधान करने में सफल हो जाती है कि 30% अधिक ऐसी इक्विटी का लगाया जाना साधारण जनता के हित में था ।

(2) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में जिनके लिए 1-4-2004 से पूर्व विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया गया था और जिनके 1-4-2004 से 31-3-2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70 : 30 के अनुपात में ऋण इक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां परियोजना के वित्तपोषण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण तथा इक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग वहां समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के लिए 30% से उच्चतर इक्विटी पर विचार कर सकेगा जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह सुस्थापित करने के लिए समर्थ हो जाती है कि 30% से उच्चतर इक्विटी का नियोजन साधारण जनता के हित में था ।

(3) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए 1-4-2004 को या उसके पश्चात् विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, टैरिफ के प्रयोजन के लिए 70 : 30 के अनुपात में ऋण तथा इक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी 30% से अधिक है वहां 30% से अधिक इक्विटी को काल्पनिक ऋण के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां लगाई गई इक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक ऋण तथा इक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपरोक्त खंड (1), (2) या (3) के अनुसार तय की गई ऋण ईक्विटी की रकम का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर फेरफार की संगणना के लिए किया जाएगा ।”।

13. विनियम 56 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 56 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) ऋण पूंजी पर ब्याज --

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज विनियम 20 में उपदर्शित रीति से तय बकाया ऋण पर ऋणवार संगणित किया जाएगा ;

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण को विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण के रूप में माइनस 31-3-2004 तक आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय के रूप में निकाला जाएगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर निकाला जाएगा ;

(ग) उत्पादन कंपनी ऋण को पुनःवित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगी जिससे फायदाग्राहियों के कुल फायदे में अधिक से अधिक वृद्धि हो । ऐसे पुनःवित्तपोषण की सहबद्ध लागत फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ;

(घ) ऋण संबंधी निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनःवित्तपोषण की तारीख से दर्शित किया जाएगा और उसका फायदा फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ;

(ङ) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण में पुनःवित्तपोषण से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा कोई विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के वर्षों के दौरान टैरिफ में दिया गया अवक्षयण उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तदनुसार संगणित किया जाएगा ;

(छ) उत्पादन कंपनी ऋण के वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के मद्दे कोई लाभ नहीं लेंगे ;

(ज) उत्पादन कंपनी अपने स्वविवेक से ऐसे ऋण को अपने स्वयं की लागत पर स्वैप कर सकेगी जिनमें ब्याज की नियत दर वाले ऋणों के साथ ब्याज की फ्लोटिंग दर है या उसके विपरीत है और स्वैपिंग के परिणामस्वरूप लाभ या हानियों को उत्पादन कंपनी से प्रोद्भूत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि फायदाग्राही आरंभिक रूप से संविदागत ऋण के लिए, चाहे वह ब्याज फ्लोटिंग या नियत दर पर हो, ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।”।

14. विनियम 58 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 58 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“58. अंतरा-प्रादेशिक आस्तियों के लिए प्रभारों का विभाजन : प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के एक से अधिक दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों की दशा में, प्रत्येक दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक पर उद्ग्रहणीय पारेषण प्रभार निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :

दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक द्वारा मास के लिए पारेषण प्रणाली को संदेय अन्तरा-प्रादेशिक प्रणाली के लिए पारेषण प्रभार

$$= \left[\sum_{i=1}^{12} \left(\frac{\text{टीसीआई}}{12} \right) - \text{ए आर एस सी} \right] \frac{\text{X सी एस}}{\text{एससीएल}}$$

टीसीई = क्षेत्र में i परियोजना के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार

एन = क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या

ए आर एस सी = समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए उपयुक्त प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक पारेषण ग्राहकों से मास के लिए पारेषण प्रभारों की वसूली का समायोजनीय भाग ।

सीएल = दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक को आबंटित पारेषण क्षमता ।

एससीएल = प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को आबंटित पारेषण क्षमताओं का योग ।

15. **विनियम 59 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 59 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“59. **अन्तर-प्रादेशिक आस्तियों के लिए प्रभारों का विभाजन** : अन्तर-प्रादेशिक आस्तियों के पारेषण प्रभार आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से विनिश्चित के सिवाय, निम्नानुसार बांटे जाएंगे :—

(क) ऐसे ग्राहक, जिसका आबंटन अन्य क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से हो और/ या जिनके पास अन्य क्षेत्र में ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक संविदा हो, द्वारा संदेय अन्तर-प्रादेशिक आस्ति के लिए मासिक पारेषण प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

टीएल : $(टीएससी/12) \times (सीसी/सीआईआर)$

जहां,

टीएससी = अन्तर-प्रादेशिक आस्ति के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार,

सीसी = आबंटित और/या संविदागत ऊर्जा को अंतरित करने के लिए अपेक्षित अन्तर-प्रादेशिक आस्ति की मेगावाट में क्षमता,

सीआईआर = एम डब्ल्यू में अन्तर-प्रादेशिक आस्ति की क्षमता ।

(ख) अन्तर-प्रादेशिक आस्ति की अतिशेष क्षमता में से, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र आरक्षित मार्जिन के रूप में कुछ क्षमता को रखने का विनिश्चय कर सकेगा। केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, दीर्घकालिक संविदाओं तथा आरक्षित मार्जिन से आबंटन के लिए लेखांकन करने के पश्चात् अन्तर-क्षेत्रीय लिंक की क्षमता अल्पकालिक खुली पहुंच के लिए उपलब्ध होगी। अल्पकालिक पारेषण ग्राहक समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा।

(ग) अन्तर-क्षेत्रीय आस्तियों द्वारा संयोजित दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय विश्वस्तता समर्थन के लिए पारेषण प्रभार निम्नलिखित रूप में होंगे :--

$$\text{टीआर} = 0.5 \{ (\text{टीएससी}/12) - \Sigma \text{टीएल} - \text{ए आर एस सी} \} \times (\text{सीएल}/\text{एससीएल})$$

जहां,

टीआर = अन्तर-प्रादेशिक आस्ति के जुड़ी क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा अन्तर-क्षेत्रीय आस्ति के लिए मास हेतु संदेय विश्वस्तता समर्थन प्रभार।

टीएससी = अन्तर-क्षेत्रीय आस्ति के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार।

$\Sigma \text{टीएल}$ = केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से आबंटित ऊर्जा के अन्तरण के लिए अन्तर-क्षेत्रीय आस्ति या दीर्घकालिक करार के परिणामस्वरूप उपलब्ध ऊर्जा के उपयोग के लिए मास के लिए संदेय कुल पारेषण प्रभार।

एआरएससी = अल्पकालिक पारेषण ग्राहकों से मास के लिए बसूले गए राजस्व का समायोजनीय भाग जिसका उपयोग समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती करने के लिए किया जाता है।

सीएल = क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक ग्राहक को आबंटित पारेषण क्षमता जिसमें वह अवस्थित है, और

एससीएल = क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों की आबंटित पारेषण क्षमताओं का योग जिसमें वह अवस्थित है ।”।

16. विनियम 62 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 62 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“62. विलम्ब संदाय अधिभार : यदि बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद फायदाग्राहियों द्वारा किसी बिल के संदाय में विलम्ब किया जाता है तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिमास 1.25% की दर से विलम्ब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।” ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन III/IV/150/2006/असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2006

No. L-7/25(5)/2003-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004, hereinafter referred to as “the principal regulations”, namely :—

1. **Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Insertion of Regulation 5A:** After Regulation 5 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely:-

“5A. **Provisional tariff :** Provisional tariff or provisional billing of charges, wherever allowed by the Commission based on the application made by the generating company or the transmission licensee or by the Commission on its

own motion or otherwise, shall be adjusted against the final tariff approved by the Commission.

Provided that where the provisional tariff charged exceeds the final tariff approved by the Commission under these regulations, the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall pay simple interest @ 6% per annum, computed on monthly basis, on the excess amount so charged, from the date of payment of such excess amount and up to the date of adjustment.

Provided further that where the provisional tariff charged is less than the final tariff approved by the Commission, the beneficiaries shall pay simple interest @ 6% per annum, computed on monthly basis on the deficit amount from the date on which final tariff will be applicable up to the date of billing of such deficit amount.

Provided also that excess/deficit amount along with simple interest @ 6% shall be adjusted within three months from the date of the order failing which the defaulting utility/beneficiary shall be liable to pay penal interest on excess/deficit amount at the rate as may be decided by the Commission."

3. **Amendment of Regulation 20:** For Regulation 20 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"20. **Debt-Equity Ratio.** (1) In case of the existing generating stations, debt-equity ratio considered by the Commission for the period ending 31.3.2004 shall be considered for determination of tariff with effect from 1.4.2004:

Provided that in cases where the tariff for the period ending 31.3.2004 has not been determined by the Commission, debt-equity ratio shall be as may be decided by the Commission:

Provided further that in case of the existing generating stations where additional capitalisation has been completed on or after 1.4.2004 and admitted by the Commission under Regulation 18, equity in the additional capitalization to be considered shall be,-

- (a) 30% of the additional capital expenditure admitted by the Commission; or
 - (b) equity approved by the competent authority in the financial package, for additional capitalization; or
 - (c) actual equity employed,
- whichever is the least:

Provided further that in case of additional capital expenditure admitted under the second proviso, the Commission may consider equity of more than 30% if the generating company is able to satisfy the Commission that deployment of such equity of more than 30% was in the interest of general public.

(2) In case of the generating stations for which investment approval was accorded prior to 1.4.2004 and which are likely to be declared under commercial operation during the period 1.4.2004 to 31.3.2009, debt and equity in the ratio of 70:30 shall be considered:

Provided that where equity actually employed to finance the project is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of tariff:

Provided further that the Commission may in appropriate cases consider equity higher than 30% for determination of tariff, where the generating company is able to establish to the satisfaction of the Commission that deployment of equity higher than 30% was in the interest of general public.

(3) In case of the generating stations for which investment approval is accorded on or after 1.4.2004, debt and equity in the ratio of 70:30 shall be considered for determination of tariff:

Provided that where equity actually employed is more than 30%, equity in excess of 30% shall be treated as notional loan:

Provided further that where deployment of equity is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of tariff.

(4) The debt and equity amount arrived at in accordance with above clause (1), (2) or (3), as the case may be, shall be used for calculation of interest on loan, return on equity, advance against depreciation and foreign exchange rate variation."

4. **Amendment of Regulation 21:** For Clause (i) of Regulation 21 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Interest on loan capital**

(a) Interest on loan capital shall be computed loan-wise on the loans arrived at in the manner indicated in Regulation 20;

(b) The loan outstanding as on 1.4.2004 shall be worked out as the gross loan in accordance with Regulation 20 minus cumulative repayment as admitted by the Commission or any other authority having power to do so, up to 31.3.2004. The repayment for the period 2004-09 shall be worked out on a normative basis;

(c) The generating company shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net benefit to the beneficiaries. The costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries;

(d) The changes to the loan terms and conditions shall be reflected from the date of such re-financing and benefit passed on to the beneficiaries;

- (e) In case of dispute, any of the parties may approach the Commission with proper application. However, the beneficiaries shall not withhold any payment ordered by the Commission to the generating company during pendency of any dispute relating to re-financing of loan;
- (f) In case any moratorium period is availed of by the generating company, depreciation provided for in the tariff during the years of moratorium shall be treated as repayment during those years and interest on loan capital shall be calculated accordingly;
- (g) The generating company shall not make any profit on account of re-financing of loan and interest on loan;
- (h) The generating company may, at its discretion, swap loans having floating rate of interest with loans having fixed rate of interest, or vice-versa, at its own cost and gains or losses as a result of such swapping shall accrue to the generating company:

Provided that the beneficiaries shall be liable to pay interest for the loans initially contracted, whether on floating or fixed rate of interest."

5. **Amendment of Regulation 26:** For Regulation 26 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"26. **Late Payment Surcharge:** In case the payment of any bill (other than UI and VAR charges) is delayed by the beneficiary(ies) beyond a period of 60 days from the date of billing, a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the generating company."

6. **Amendment of Regulation 36:** For Regulation 36 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"36. **Debt-Equity Ratio.** (1) In case of the existing generating stations, debt-equity ratio considered by the Commission for the period ending 31.3.2004, shall be considered for determination of tariff with effect from 1.4.2004:

Provided that in cases where the tariff for the period ending 31.3.2004
has not been determined by the Commission, debt-equity ratio shall be as may
be decided by the Commission:

Provided further that in case of the existing generating stations where
additional capitalisation has been completed on or after 1.4.2004 and admitted
by the Commission under Regulation 34, equity in the additional capitalization
to be considered shall be,-

- (a) 30% of the additional capital expenditure admitted by the
Commission, or
- (b) equity approved by the competent authority in the financial
package, for additional capitalization, or
- (c) actual equity employed,

whichever is the least:

Provided further that in case of additional capital expenditure admitted
under the second proviso, the Commission may consider equity of more than
30% if the generating company is able to satisfy the Commission that
deployment of such equity of more than 30% was in the interest of general
public.

(2) In case of the generating stations for which investment approval was
accorded prior to 1.4.2004 and which are likely to be declared under
commercial operation during the period 1.4.2004 to 31.3.2009, debt and equity
in the ratio of 70:30 shall be considered:

Provided that where equity actually employed to finance the project is
less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination
of tariff:

Provided further that the Commission may in appropriate cases consider
equity higher than 30% for determination of tariff, where the generating

company is able to establish to the satisfaction of the Commission that deployment of equity higher than 30% was in the interest of general public.

(3) In case of the generating stations for which investment approval is accorded on or after 1.4.2004, debt and equity in the ratio of 70:30 shall be considered for determination of tariff:

Provided that where equity actually employed is more than 30%, equity in excess of 30% shall be treated as notional loan;

Provided further that where deployment of equity is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of tariff.

(4) The debt and equity amount arrived at in accordance with above clause (1), (2) or (3), as the case may be, shall be used for calculation of interest on loan, return on equity, advance against depreciation and foreign exchange rate variation."

7. **Amendment of Regulation 38:** For Clause (i) of Regulation 38 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Interest on loan capital**

(a) Interest on loan capital shall be computed loan wise on the loans arrived at in the manner indicated in Regulation 36;

(b) The loan outstanding as on 1.4.2004 shall be worked out as the gross loan in accordance with Regulation 36 minus cumulative repayment as admitted by the Commission or any other authority having power to do so, up to 31.3.2004. The repayment for the period 2004-09 shall be worked out on a normative basis;

(c) The generating company shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net benefit to the beneficiaries. The costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries;

(d) The changes to the loan terms and conditions shall be reflected from the date of such re-financing and benefit passed on to the beneficiaries;

(e) In case of dispute, any of the parties may approach the Commission with proper application. However, the beneficiaries shall not withhold any payment ordered by the Commission to the generating company during pendency of any dispute relating to re-financing of loan;

(f) In case any moratorium period is availed of by the generating company, depreciation provided for in the tariff during the years of moratorium shall be treated as repayment during those years and interest on loan capital shall be calculated accordingly;

(g) The generating company shall not make any profit on account of re-financing of loan and interest on loan;

(h) The generating company may, at its discretion, swap loans having floating rate of interest with loans having fixed rate of interest, or vice-versa, at its own cost, and gains or losses as a result of such swapping shall accrue to the generating company:

Provided that the beneficiaries shall be liable to pay interest for the loans initially contracted, whether on floating or fixed rate of interest."

8. **Amendment of Regulation 39:** For clause (2) and (3) of regulation 39 of the principal regulations the following shall be substituted, namely:-

"(2) Rate of primary energy for all hydro electric power generating stations, except for pumped storage generating stations, shall be equal to average of the lowest variable charges of the central sector thermal power generating station of the concerned region for all months of the previous year. The primary energy charge shall be computed based on the primary energy rate and saleable scheduled primary energy of the station:

Provided that in case the primary energy charge recoverable by applying the above primary energy rate exceeds the Annual fixed charges of a generating station, the primary energy rate for such generating station shall be calculated by the following formula:

$$\text{Primary energy rate} = \frac{\text{Annual Fixed Charge}}{\text{Saleable design energy}}$$

$$(3) \text{ Primary Energy Charge} = \text{Saleable Scheduled Primary Energy} \times \text{Primary Energy Rate.}$$

Secondary Energy Rate shall be equal to the primary Energy Rate.

$$\text{Secondary Energy Charge} = \text{Saleable scheduled Secondary Energy} \times \text{Secondary Energy Rate.}''$$

9. **Amendment of Regulations 40:** For clause (4) of Regulation 40 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"(4) The total incentive payment calculated on annual basis shall be shared by the beneficiaries based on the saleable allocated capacity."

10. **Amendment of Regulation 44:** For Regulation 44 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"44. **Late Payment Surcharge:** In case the payment of any bill (other than UI and VAR charges) is delayed by the beneficiary(ies) beyond a period of 60 days from the date of billing, a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the generating company."

11. **Amendment of Regulation 48:** For clause (iv) of Regulation 48 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"(iv) The capacity charges shall be paid by the beneficiary(ies) including those outside the region to the generating company every month in accordance

with the following formulas and in proportion to their respective shares in the concerned generating station:

ACC1	=AFC-(SPE1+DE 2 nd to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC2	=AFC-(SPE2+DE 3 rd to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC3	=AFC-(SPE3+DE 4 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC4	=AFC-(SPE4+DE 5 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC5	=AFC-(SPE5+DE 6 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC6	=AFC-(SPE6+DE 7 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC7	=AFC-(SPE7+DE 8 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC8	=AFC-(SPE8+DE 9 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC9	=AFC-(SPE9+DE 10 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC10	=AFC-(SPE10+DE 11 th to 12 th months)* Primary Energy Rate
ACC11	=AFC-(SPE11+DE 12 th month)* Primary Energy Rate
ACC12	=AFC-(SPE12)* Primary Energy Rate

Where,

AFC= Annual Fixed Charges

ACC1, ACC2, ACC3, ACC4, ACC5, ACC6, ACC7, ACC8, ACC9, ACC10, ACC11 and ACC12 are the amount of Annual Capacity Charge for the cumulative period up to the end of 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th month respectively.

SPE1, SPE2, SPE3.....SPE12 are the ex-bus saleable scheduled primary energy values up to 1st, 2nd, 3rd.....12th months of the year respectively.

$$CC1 = \frac{ACC1 \times DE1}{DE}$$

$$CC2 = \frac{ACC2 \times DE2}{DE}$$

$$CC3 = \frac{ACC3 \times DE3}{DE}$$

$$CC4 = \frac{ACC4 \times DE4}{DE}$$

$$CC5 = \frac{ACC5 \times DE5}{DE}$$

$$CC6 = \frac{ACC6 \times DE6}{DE}$$

$$CC7 = \frac{ACC7 \times DE7}{DE}$$

$$CC8 = \frac{ACC8 \times DE8}{DE}$$

$$CC9 = \frac{ACC9 \times DE9}{DE}$$

$$CC10 = \frac{ACC10 \times DE10}{DE}$$

$$CC11 = \frac{ACC11 \times DE11}{DE}$$

$$CC12 = \frac{ACC12 \times DE12}{DE}$$

Where,

CC1, CC2, CC3, CC12 is the monthly capacity charge up to 1st, 2nd, 3rd, 12th month of the year respectively.

DE = Annual saleable Design Energy

DE1, DE2, DE3, DE12 are the ex-bus saleable design energy values up to 1st, 2nd, 3rd, 12th month of the year respectively..

Total capacity charges payable to the generator for the:

$$1^{\text{st}} \text{ month} = (CC1)$$

$$2^{\text{nd}} \text{ month} = (CC2 - CC1)$$

$$3^{\text{rd}} \text{ month} = (CC3 - CC2)$$

$$4^{\text{th}} \text{ month} = (CC4 - CC3)$$

$$5^{\text{th}} \text{ month} = (CC5 - CC4)$$

$$6^{\text{th}} \text{ month} = (CC6 - CC5)$$

7th month $=(CC7-CC6)$

8th month $=(CC8-CC7)$

9th month $=(CC9-CC8)$

10th month $=(CC10-CC9)$

11th month $=(CC11-CC10)$

12th month $=(CC12-CC11)$

and, each beneficiary having firm allocation in capacity of the generating station shall pay for the:

1st month $=[CC1XWB1]/100$

2nd month $=[CC2XWB2-CC1XWB1]/100$

3rd month $=[CC3XWB3-CC2XWB2]/100$

4th month $=[CC4XWB4-CC3XWB3]/100$

5th month $=[CC5XWB5-CC4XWB4]/100$

6th month $=[CC6XWB6-CC5XWB5]/100$

7th month $=[CC7XWB7-CC6XWB6]/100$

8th month $=[CC8XWB8-CC7XWB7]/100$

9th month $=[CC9XWB9-CC8XWB8]/100$

10th month $=[CC10XWB10-CC9XWB9]/100$

11th month $=[CC11XWB11-CC10XWB10]/100$

12th month $=[CC12XWB12-CC11XWB11]/100$

Where,

And WB1, WB2, WB3, WB4, WB5, WB6, WB7, WB8, WB9, WB10, WB11, and WB12 are the weighted average of percentage saleable allocated capacity share of the beneficiary during the cumulative period up to 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th month respectively."

12. Amendment of Regulation 54: For Regulation 54 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"54. Debt-Equity Ratio. (1) In case of the existing projects, debt-equity ratio considered by the Commission for the period ending 31.3.2004 shall be considered for determination of tariff with effect from 1.4.2004:

Provided that in cases where the tariff for the period ending 31.3.2004 has not been determined by the Commission, debt-equity ratio shall be as may be decided by the Commission:

Provided further that in case of the existing projects where additional capitalisation has been completed on or after 1.4.2004 and admitted by the Commission under Regulation 53, equity in the additional capitalization to be considered shall be,-

- (a) 30% of the additional capital expenditure admitted by the Commission, or
 - (b) equity approved by the competent authority in the financial package, for additional capitalization, or
 - (c) actual equity employed,
- whichever is the least:

Provided further that in case of additional capital expenditure admitted under the second proviso, the Commission may consider equity of more than 30% if the transmission licensee is able to satisfy the Commission that deployment of such equity of more than 30% was in the interest of general public

(2) In case of the transmission systems for which investment approval was accorded prior to 1.4.2004 and which are likely to be declared under commercial operation during the period 1.4.2004 to 31.3.2009, debt and equity in the ratio of 70:30 shall be considered:

Provided that where equity actually employed to finance the project is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of tariff:

Provided further that the Commission may in appropriate cases consider equity higher than 30% for determination of tariff, where the generating company is able to establish to the satisfaction of the Commission that deployment of equity higher than 30% was in the interest of general public.

(3) In case of the transmission systems for which investment approval is accorded on or after 1.4.2004, debt and equity in the ratio of 70:30 shall be considered for determination of tariff.

Provided that where equity actually employed is more than 30%, equity in excess of 30% shall be treated as notional loan:

Provided further that where deployment of equity is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of tariff.

(4) The debt and equity amount arrived at in accordance with above clause (1), (2) or (3), as the case may be, shall be used for calculation of interest on loan, return on equity, advance against depreciation and foreign exchange rate variation."

13. **Amendment of Regulation 56:** For Clause (i) of 56 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Interest on loan capital**

(a) Interest on loan capital shall be computed loan wise on the loans arrived at in the manner indicated in Regulation 54;

(b) The loan outstanding as on 1.4.2004 shall be worked out as the gross loan in accordance with Regulation 54 minus cumulative repayment as admitted by the Commission or any other authority having

power to do so, up to 31.3.2004. The repayment for the period 2004-09 shall be worked out on a normative basis;

(c) The transmission licensee shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net benefit to the beneficiaries. The costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries;

(d) The changes to the loan terms and conditions shall be reflected from the date of such re-financing and benefit passed on to the beneficiaries;

(e) In case of dispute, any of the parties may approach the Commission with proper application. However, the beneficiaries shall not withhold any payment ordered by the Commission to the transmission licensee during pendency of any dispute relating to re-financing of loan;

(f) In case any moratorium period is availed of by the transmission licensee, depreciation provided for in the tariff during the years of moratorium shall be treated as repayment during those years and interest on loan capital shall be calculated accordingly;

(g) The transmission licensee shall not make any profit on account of re-financing of loan and interest on loan;

(h) The transmission licensee may, at its discretion, swap loans having floating rate of interest with loans having fixed rate of interest, or vice versa, at its own cost and gains or losses as a result of such swapping shall accrue to the transmission licensee;

Provided that the beneficiaries shall be liable to pay interest for the loans initially contracted, whether on floating or fixed rate of interest."

14. **Amendment to Regulation 58:** For Regulation 58 of the principal regulations, the following shall be substituted, namely:-

"58. **Sharing of charges for intra-regional assets:** In case of more than one long-term transmission customer of the regional transmission system, the transmission charges leviable on each long-term transmission customer shall be computed in accordance with the following formula:

Transmission Charges for intra-regional system payable for a month by a long-term transmission customer of that transmission system

$$= \left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{TCI}{12} \right] - ARSC \right) \times \frac{CL}{SCL}$$

Where

TCI = Annual Transmission Charges for the i^{th} project in the region.

n = Number of projects in the region

ARSC = Adjustable part of the recovery of transmission charges for the month from Short-term transmission customers for the regional transmission system used for reduction in transmission charges payable by long-term transmission customers in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2004 as amended from time to time.

CL = Allotted Transmission Capacity to the long-term transmission customer

SCL = Sum of the Allotted Transmission Capacities to all the long-term transmission customers of the regional transmission system."

15. **Amendment to Regulation 59:** For Regulation 59 of the principal regulations the following shall be substituted, namely:

"59. Sharing of charges for inter-regional assets: The transmission charges of the inter-regional assets shall be shared as under, except as specifically decided otherwise by the Commission,-

- (a) The monthly transmission charges for an inter-regional asset payable by a customer having allocation from the Central Generating Station located in the other region and/or having long-term contract for power in the other region shall be:

$$TL = (TSC/12) \times (CC/CIR)$$

Where

TSC = Annual Transmission Charges for the inter-regional asset,

CC = Capacity in MW of the inter-regional asset required for transferring allocated and/or contracted power,

CIR = Capacity of the inter-regional asset in MW;

- (b) Out of the balance capacity of the inter-regional asset, Regional Load Despatch Centres may decide to keep certain capacity as a reserve margin. The capacity of the inter-regional link after accounting for allocation from Central Generating Stations, long-term contracts and reserve margin shall be made available for short-term open access. The short-term transmission customers shall pay transmission charges as per Central Electricity Regulatory Commission (Open access in inter-State Transmission) Regulations, 2004 as amended from time to time;
- (c) The transmission charges for reliability support payable by long-term customers of the regional transmission system of the two regions connected by the inter-regional assets shall be as under:

$$T_r = 0.5 \times \{ (TSC/12) - \sum TL - ARSC \} \times (CL/SCL)$$

Where

T_r = Reliability support charges payable for the month for inter-regional asset by a long-term customer of regional transmission system connected to the inter-regional asset;

TSC = Annual transmission charges for the inter-regional asset;

$\sum TL$ = Total transmission charges payable for the month for use of the inter-regional asset for transfer of allocated power from Central Generating Station or power available consequent to a long-term agreement;

ARSC = Adjustable part of the revenue recovery for the month from short-term transmission customers, which is used for reduction in transmission charges payable by long-term transmission customers in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Open access in inter-State Transmission) Regulations, 2004 as amended from time to time;

CL = Allotted Transmission capacity to the long-term customer in the regional transmission system in which it is located; and

SCL = Sum of the Allotted Transmission Capacities of all long-term transmission customers of the regional transmission system in which it is located "

16. **Amendment to Regulation 62:** For Regulation 62 of the principal regulations the following shall be substituted, namely:

"62. **Late payment surcharge :** In case the payment of any bill is delayed by the beneficiary(ies) beyond a period of 60 days from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the transmission licensee."

A.K. SACHAN, Secy.

[ADVT III/IV/150/2006/Exty.]